

## क्या रूस-अमरीका के बीच 'ट्रेड वॉर' छड़ि जाएगा

### संदर्भ

गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्तावति वधियक पर हस्ताक्षर किये हैं। ध्यातव्य है कि इस वधियक को सीनेट की मंजूरी पहले ही प्राप्त हो गई है।

### प्रमुख बदि

- वधियक में ईरान और उत्तर कोरिया पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- इस वधियक की सबसे खास बात यह है कि इसने राष्ट्रपति ट्रंप की उन शक्तियों को सीमति कर दिया गया है, जिसे वह रूस पर लगे प्रतिबंधों को खुद-ब-खुद वापस ले सकते थे।
- वस्तुतः इस वधियक का उद्देश्य गत वर्ष हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथति दखलंदाजी और सीरिया और यूक्रेन में आक्रामकता के लिये रूस को दंडति करना है।

### रूस की प्रतिक्रिया

- गौरतलब है कि उक्त प्रतिबंधों के संबंध में रूस के द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। रूस के प्रधानमंत्री दमित्रि मेदवेदेव के कथनानुसार, ऐसा नरिणय करके अमेरिका ने रूस के खिलाफ पूरी तरह से व्यापारिक जंग का एलान किया है।
- ईरान ने स्वयं पर अधिपति प्रतिबंधों के संबंध में कहा है कि ये नए प्रतिबंध परमाणु समझौते में वर्णति प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और वह अमेरिका के इस नरिणय का उचित एवं सही तरीके से जवाब देगा।
- ध्यातव्य है कि रूस शुरुआत से ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में उसकी किसी भी तरह की दखलंदाजी से इनकार करता रहा है। हालाँकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भी इन आरोपों को हमेशा खारजि किया गया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का यह कदम बहुत से प्रश्नों को जन्म देता है। वस्तुतः विश्व की दो महाशक्तियों के बीच उभरी यह स्थिति समस्त विश्व के लिये चिंता का वषिय है।
- इसी क्रम में अमेरिका द्वारा अधिपति प्रतिबंधों की जवाबी कार्रवाई के रूप में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को रूस छोड़ने को कहा।
- वस्तुतः रूस का यह कदम इस बात की ओर इशारा करता है कि इन दोनों देशों के बीच संबंधों का यह एक कठनि दौर है। अब देखना यह होगा कि इसका विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है?

### प्रभाव

- गौरतलब है कि अमेरिका के इस कदम के बाद अमेरिकियों के लिये रूसी एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश करना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियों के लिये रूस में व्यापार करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा।
- इस मामले में जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र विशेष पर पड़ने वाले आर्थिक दुष्परणामों की आशंका व्यक्त की है।